

HRA IN UNIVA The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3---उप-खांड (i) PART II---Section 3---Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 298] No. 298] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 1996/भाद्र 27, 1918 NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 1996/BHADRA 27, 1918

वित्त मंत्रालय

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1996

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1996

सा.का.नि. 426(अ).—अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 245फ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1996 है।
- 2. ये तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) ''अधिनियम'' से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) से अभिप्रेत है;
 - (ख) ''अग्रिम विनिर्णय'' से अधिनियम की धारा 245ढ के उपखंड (क) में यथापरिभाषित अग्रिम विनिर्णय अभिप्रेत हैं;
 - (ग) ''आवेदक'' से अधिनियम की धारा 245ढ के उपखंड (ख) में यथापरिभाषित आवेदक अभिप्रेत है;
 - (घ) "आवेदन" से अधिनियम की धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन आवेदन अभिप्रेत हैं, किन्तु जहां संदर्भ से ऐसा अनुज्ञात हो, वहां इसके अंतर्गत नियम 5 में निर्दिष्ट प्रकार के सभी आवेदन, अर्जी और अभ्यावेदन होंगे;
 - (ङ) "प्राधिकृत प्रतिनिधि":--

- (i) का, किसी आवेदक के संबंध में वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में है, मानो आवेदक एक निर्धारिती हो:
- (ii) से, आयुक्त के संबंध में, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जिसे; आयुक्त द्वारा लिखित रूप में प्राधिकरण के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में आयुक्त की ओर से उपसंजात होने, अमिवाक् और कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाए:
- (च) ''प्राधिकरण'' से अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित अगिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत हैं;
- (छ) ''मामले'' से किसी आवेदक के संबंध में अधिनियम के अध्याय 19-ख के अधीन कोई कार्यवाही अभिप्रेत है;
- (ज) ''अध्यक्ष'' से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेतं है;
- (ञ्च) ''आयुक्त'' से अभिप्रेत है :
 - (i) आयकर अधिनियम के अधीन निर्धारित किसी आवेदक के संबंध में अधिनियम की धारा 2 के उपखंड (16) में यथापरिभाषित आयुक्त,
 - (ii) किसी ऐसे आवेदक की बाबत, जिसे अब तक निर्धारित नहीं किया गया है, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस निमित्त पदाभिष्टित आयुक्त.
- (त्र) ''सदस्य'' से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष हैं;
- (ट) ''आदेश'' के अन्तर्गत प्राधिकरण का कोई आदेश, निदेश या विनिर्णय है;
- (ठ) "नियम" से अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (प्रक्रिया) नियम,1996 का कोई नियम अभिप्रेत है;
- (इ) ''सचिव'' से प्राधिकरण के सचिव के रूप में पदाभिष्टित आयकर आयुक्त अभिप्रेत हैं और जहां संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, वहां

इम्प्के अन्तर्गत सचिव की उसके कृत्यों में सहायक करने के लिए नियुक्त अपर आयकर आयुक्त और उप आयकर आयुक्त हैं;

- (ह) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (ण) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और पिरभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में पिरभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।
- 3. प्राधिकरण की भाषा:—(1) प्राधिकरण की भाषा साधारणतया अंग्रेजी होगी: परन्तु प्राधिकरण, पक्षकारों के अनुरोध पर, अपने समक्ष कार्यवाहियों में हिन्दी का प्रयोग उस सीमा तक कर सकेगा जितनी वह उपयुक्त और व्यावहारिक समझे।
- (2) जहां कोई दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी से भिन्न भाषा में है वहां उसके साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी दाखिल किया जाना चाहिए।
- (3) प्राधिकरण का विनिर्णय और उसके द्वारा पारित अन्य आदेश, प्राधिकरण के विवेक पर, हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।
- 4. प्राधिकरण की बैठकें : प्राधिकरण अपनी बैठकें, दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में या ऐसे अन्य स्थानों पर, जो अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, करेगा तथा सुनवाई की तारीख और स्थान ऐसी रीति से, जो अध्यक्ष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे, अधिसूचित किया जाएगा।
- 5. प्राधिकरण की शिक्तियां: —प्राधिकरण अधिनियम की धारा 245थ की उपधारा (1) के अधीन दिए गए आवेदन की और अंतवर्ती आनुषंगिक या प्रासांगिक प्रकार के ऐसे अन्य आवेदनों, अर्जियों और अध्यावेदनों की, जो आवेदन के पूर्ण और प्रभावी निपटारे के लिए आवश्यक हों, जो अध्यक्ष, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निदेश दे, सुनवाई करेगा और उनका अवधारण करेगा।
- 6. किठिनाई दूर करने की शिक्त : यदि प्राधिकरण के किसी आदेश को प्रभावी करने में कोई किठनाई उत्पन्न होती है, तो प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से अथवा आवेदक या आयुक्त द्वारा दिए गए आवेदन पर उस किठनाई को दूर करेगा, जहां तक वह अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है।
- 7. सचिव की शिक्तयां और कृत्य:—(1) प्राधिकरण के अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में होंगे और वह ऐसे अन्य कृत्य, जो इन नियमों के अधीन या अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा, पृथक आदेश द्वारा उसे सींपे जाएं, करेगा।
- (2) प्राधिकरण की प्राधिकारिक मुद्रा सचिव की अभिरक्षा में रखी जाएगी।
- (3) सिचव की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तब्य भी होंगे, अर्थात्:--
 - (i) प्राधिकरण के समक्ष दाखिल किए गए सभी आवेदन प्राप्त करना;
 - (ii) आवेदन की यह पता लगाने के लिए संवीक्षा करना कि क्या वे अधिनियम, नियमों और प्रक्रिया के अनुरूप हैं;
 - (iii) ऐसं आवेदन में त्रुटियों के बारे में पक्षकारों को बताना और उन्हें त्रुटियों को दूर करने के लिए उचित अवसर प्रदान करके उनसे ऐसा करने की अपेक्षा करना और जहां दिए

- गए समय के भीतर त्रुटियां दूर नहीं की जातीं वहां प्राधिकरण से आवश्यक आदेश अभिप्राप्त करना;
- (iv) आवेदन की सुनवाई की तारीख अध्यक्ष के परामर्श से नियत करना और उसकी सूचनाएं जारी करने के लिए निदेश देना;
- (v) सृच्नाओं और अन्य प्रक्रियाओं की तामील कराना और यह सुनिश्चित करना कि वे पक्षकारों को उचित रूप से तामील कर दी गई हैं;
- (vi) किसी व्यक्ति की, जिसके अन्तर्गत आयुक्त या कोई अन्य प्राधिकारी है, अभिरक्षा से अभिलेखों की सपेक्षा करना;
- (vii) प्राधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण अनुज्ञात करना;
- (viii) प्राधिकरण के अभिलेखों के किसी औपचारिक संशोधन का निदेश देना;
- (ix) प्राधिकरण के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां पक्षकारों को देना;
- (x) कार्यवाहियों में दाखिल किए गए दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां नियमों के अनुसार पक्षकारों को देना;
- (xi) कार्यवाहियों में किसी पक्षकार की मृत्यु या निवर्तन की दशा में विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख में लाना और मामला सूची में ऐसे उपयुक्त संशोधन करना जो नियम 15 में निर्दिष्ट अन्य स्थितियों में आवश्यक हो जाएं।
- 8. सूचनाओं, आदि पर हस्ताक्षर किया जाना:—(1) प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाली अपेक्षा, निदेश, पत्र, प्राधिकार या लिखित सूचना पर सचिव द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (2) उपनियम (1) की कोई बात, किसी ऐसी अपेक्षा या निदेश को, जो प्राधिकरण सुनवाई के दौरान किसी आवेदक को या प्राधिकृत प्रतिनिधि को जारी करे, लागू नहीं होगी।
- 9. सूचनाओं की तामील का ढंग:— किसी व्यक्ति को तामील या पारिदत्त की जाने के अपेक्षित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज, आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से दस्ती द्वारा या रिजस्ट्रीकृत डाक द्वारा या उस व्यक्ति या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को फैक्स द्वारा तामील के लिए उसके द्वारा दिए गए पते या फैक्स संख्यांक पर या उस स्थान पर, जहां वह व्यक्ति प्राधिकृत प्रतिनिधि साधारणतया निवास करता है या कारोबार करता है या वैयक्तिक रूप से अभिलाभ के लिए कार्य करता है, भेजा जाएगा।
- 10. आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया :—(1) आवेदन, आयकर नियम, 1962 के प्ररूप 34ग में चार प्रतियों में किया जाएगा और आवेदक द्वारा, वैयक्तिक रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सचिव द्वारा लिखित रूप में अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी को नई दिल्ली में संदेय 'अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण' के पक्ष में लिखे गए मांग इाफ्ट के रूप दो हजार पांच सौ भारतीय रुपयों में फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा या सचिव के पते पर राजस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा।
- (2) आवेदन, उसका सत्यापन और इसके साथ उपाबंध, विवरण और दस्तावेज आयकर नियम, 1962 के नियम 44 के उपनियम (2) में उपवर्णित रीति से हस्ताक्षरित किए जाएंगे:

परन्तु जहां आवेदन और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति यह दावा करता है कि वह नियमों के अधीन उस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत है वहां आवेदन के साथ उसको उसके हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करने वाला, मुख्तारनाम। और उस अपिरहार्य कारण को, जो उसको हस्ताक्षर करने के लिए हकदार बनाता है, उपवर्णित करने वाला, शपथपत्र होना चाहिए:

- (3) उपनियम (1) के अधीन रिजस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा गया आवेदन उस तारीख को किया गया समझा जाएगा जिसको वह प्राधिकरण के कार्यालय में प्राप्त होता है।
- (4) यदि आवेदक को अब तक भारत में निर्धारित नहीं किया गया है तो, वह आवेदन के उपबंध में उपदर्शित करेगा :
 - (क) किसी अन्य देश में उसका प्रधान कार्यालय;
 - (ख्र) भारत में वह स्थान जहां उसका कार्यालय और निवास अवस्थित है या अवस्थित होने की संभावना है, और
 - (ग) भारत में उसके प्रतिनिधि का, यदि कोई है, नाम और पता जो सूचनाएं और कागजपत्र उसकी ओर से प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।
- (5) यदि आवेदन किसी भी रूप में त्रुटियों को ऐसे समय के भीतर, जो वह अनुज्ञात करे, दूर करने के लिए आवेदन को आवेदक के पास भेज सकता है। ऐसा आवेदन उस तारीख को किया गया समझा जाएगा जिसको संशोधन के पश्चात् उसे पुन: प्रस्तुत किया जाता है।
- 11. प्राधिकरण के समक्ष अतिरिक्त तथ्य प्रस्तुत करना :—
 (1) प्राधिकरण, अपने विवेक पर, आवेदक को ऐसे अतिरिक्त तथ्य प्रस्तुत करने को अनुज्ञा दे सकेगा या उससे अपेक्षा कर सकेगा जो इसे विनिर्णय सुनाने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है।
- (2) जहां प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के दौरान, ऐसा तथ्य अभिकथित है जो अभिलेख में नहीं हो सकता है या अभिलेख के प्रतिकृल है, वहां उसे स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से कथित किया जाएगा और वह सम्यक् रूप से शपथ लिए हुए शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा।
- 12. आवेदन में अन्तर्शिष्ट प्रश्न : आवेदक, प्राधिकरण की इजाजत के बिना, ऐसे किसी अतिरिक्त प्रश्न के बारे में, जो आवेदन में उपवर्णित नहीं है, न तो बताएगा न ही उसके समर्थन में उसे सुना जाएगा, किन्तु प्राधिकरण आवेदन पर विनिश्चय करते समय, अपने विवेक पर, उपवर्णित प्रश्नों के ऐसे सभी पहलुओं पर विचार करेगा जो उसके विचारार्थ उठाए गए प्रश्नों के सार के संबंध में विनिर्णय सुनाने के लिए आवश्यक हों।
- 13. सुनवाई की तारीख और स्थान का अधिसूचित किया जाना :—(1) जहां धारा 245थ के अधीन आवेदन ऐसे आवेदक से प्राप्त होता है जिसे अब तक निर्धारित नहीं किया गया है और नियम 2(झ)(2) के अधीन उसके संबंध में कोई आयुक्त पदाभिहित नहीं किया गया है बहां आवेदन और उसके अनुलग्नकों की एक प्रति यह अपेक्षा करते हुए बोर्ड को अग्रेपित की जाएगी कि वह आवेदन के प्रयोजनों के लिए दो सप्ताह के भीतर आयुक्त विनिर्दिष्ट या पदाभिहित करे, जिसके न होने पर आयुक्त के सुने बिना ही आवेदन के संबंध में विनिश्चय किया जा सके।
- (2) धारा 245थ के अधीन आवेदन के प्राप्त होने पर, जिसकी बाबत नियम 2 (झ)(1) के यथापरिभाषित आयुक्त है या इस नियम के 2(झ)(2) के अधीन या उपनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा आयुक्त

पदाभिष्टित किया गया है, प्राधिकरण आवेदक और आयुक्त को आवेदन की सुनवाई की तारीख और स्थान के बारे में अधिसूचित करेगा और आवेदन की एक प्रति आयुक्त को यह अपेक्षा करते हुए अग्रेषित करेगा कि वह मामले के सुसंगत अभिलेख, आवेदन की विषयवस्तु पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई है, सिहत प्रस्तुत करे और अपना प्राधिकृत प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करे. यदि वह सुने जाने की वांछा करता है।

- 14. प्राधिकार दाखिल करना: सुनवाई में आवेदक की ओर से उपसंजात होने वाला प्राधिकृत प्रतिनिधि, सुनवाई आरंभ होने से पंहले, आवेदक की ओर से उपसंजात होने के लिए उसे प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज दाखिल करेगा और यदि वह आवेदक का नातेदार है तो दस्तावेज में उसकी आवेदक के साथ नातेदारी की प्रकृति कथित होगी या यदि वह आवेदक द्वारा, निर्यामत रूप से नियोजित व्यक्ति है तो वह हैसियत जिसमें वह उस समय नियोजित है, कथित होगी।
- 15. आबेदक की मृत्यु, आदि होने के पश्चात् कार्यवाहियों का जारी रहना:—जहां आवेदक की मृत्यु हो जाती है या उसका परिसमापन विघटन या विछिन्न या समामेलन या कोई अन्य व्यक्ति उत्तरवर्ती हो जाता है या अन्यथा समापन हो जाता है वहां आवेदन का उपशमन नहीं होगा और इस निमित किए गए आवेदन पर, यथास्थिति, आवेदन के निष्पादक, प्रशासक या अन्य विधिक प्रतिनिधि द्वारा या समापक, रिसीवर या समानुद्शिती द्वारा जारी रखने के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा, जहां उसका विचार है कि परिस्थितियां इसे न्यायोचित ठहराती हैं।
- 16. आवेदक की सुनवाई:—(1) प्राधिकरण, नियम दिन या किसी अन्य दिन को, जिस तक सुनवाई स्थगित कर दी गई हो, उन मामलों में, जिनमें आवेदन के नामंजूर करने का प्रस्ताव है या आवेदन सुने जाने का अवसर चाहता है, आवेदक ने सुने जाने का अवसर चाहा है आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की सुनवाई करेगा। प्राधिकरण आयुक्त या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के भी सुनवाई कर सकेगा, यदि वह अपना अग्रिम विनिर्णय सुनाने से पहले ऐसा आवश्यक समझे।
- (2) समुचित मामलों में, प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति से ऐसी सामग्री देने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे वह प्राधिकरण की विनिश्चय करने में सहायता करने के लिए आवश्यक समझे।
- (3) प्राधिकरण, ऐसी दशाओं में, जो मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो, आवेदन की सुनवाई स्थिगित कर सकेगा।
- 17. मामले की एकपक्षीय रूप से सुनवाई: जहां आवेदन या आयुक्त सुनवाई के लिए नियत तारीख के या किसी अन्य दिन को, जिस तक सुनवाई स्थिगित की जाए, सुनवाई के लिए अपेक्षा की जाने पर, वैयिक्तिक रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपसंजात नहीं होता है, वहां प्राधिकरण आवेदन को गुणागुण के आधार पर एकपक्षीय रूप से निपटा सकेगा:

परन्तु जहां उपर्युक्त के अनुसार किसी आवेदन का निपटारा किया जाता है और यथास्थिति आवेदक या आयुक्त, आदेश के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर आवेदन करता है और प्राधिकरण का समाधान कर देता है कि जब आवेदन सुनवाई के लिए अपेक्षित था तो उसके उपसंजात न होने के लिए पर्याप्त कारण था वहां प्राधिकरण, विरोधी पक्षकार को सुने जाने का उचित अवसर देकर, एकपक्षीय आदेश को अपास्त करते हुए आदेश कर सकेगा और नई सुनवाई के लिए आवेदन को प्रत्यावर्तित कर सकेगा।

- 18. आदेश का उपांतरण: जहां प्राधिकरण, स्थप्रेरणा से या आवेदक या आयुक्त द्वारा उसे किए गए अभ्यावेदन पर या अन्यथा, किन्तु प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए विनिर्णय को निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यान्वित किए जाने से पहले, यह निष्कर्ष निकालता है कि उस विधि या उन तथ्यों में, जिनके आधार पर विनिर्णय सुनाया गया था, तबदीली है, वहां वह आवेदक या आयुक्त को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् उस बाबत, जिसे वह उपयुक्त समझे, आदेश द्वारा, ऐसे विनिर्णय को उपान्तरित कर सकेगा।
- 19. भूलों की परिशृद्धि:—(1) प्राधिकरण, अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशृद्धि करने की दृष्टि से, उसके द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को, प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए विनिर्णय को निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यान्वित करने से पूर्व संशोधित कर सकेगा।
- (2) ऐसा संशोधन, स्वप्रेरणा से या जब आवेदक या आयुक्त द्वारा भूल को उसकी जानकारी में लाया जाए, किया जा सकेगा, किन्तु ऐसा आवेदक या आयुक्त को सुने जाने का उचित अवसर देने के पश्चात् ही किया जा सकेगा।
- 20. अभिलेख का संशोधन : यदि प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर यह प्रतीत होता है कि अभिलेखों में कोई तथ्यक् या तात्विक गलती है, तो उसे आवेदक और आयुक्त की सुनवाई के पश्चात् संशोधित किया जाएगा।
- 21. अतिरिक्त प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय के लिए फीस:—
 (1) सचिव, आवेदक या आयुक्त द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर दस्तावेजों या आदेशों की अतिरिक्त प्रमाणित प्रतियां देने का आदेश कर सकेगा।
- (2) आवेदक से अतिरिक्त प्रमाणित प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रतिलिपि फीस तीन रुपये प्रति पृष्ठ की दर से प्रभारित की जाएगी और ऐसी फीस नकद रूप में अग्रिम रूप से संदत्त की जाएगी।
- 22. अभिलेखों का निरीक्षण और उनकी फीस:—(1) आवेदक या आयुक्त या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को सचिव को लिखित रूप में आवेदन करने पर मामले के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा, परन्तु केवल उन्हीं दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जिन पर प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में निर्भर किया गया है।
- (2) निरीक्षण केवल प्राधिकरण के किसी अधिकारी की उपस्थित में किया जाएगा और आवेदक को निरीक्षण के टिप्पण बनाने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा न कि किसी दस्तावेज की प्रतियां ले जाने के लिए।
- (3) प्राधिकरण के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए फीस आवेदक से निम्नलिखित रूप में प्रभारित की जाएगी:
 - (क) पहले घंटे या उसके भाग के लिए एक सौ रुपये; और
 - (অ) प्रत्येक अतिरिक्त घंटे या उसके भाग के लिए पचास रुपये।
- (4) निरीक्षण के लिए फीस नकद रूप में अग्रिम रूप से संदत्त की जाएगी।

- 23. अग्रिम विनिर्णय की घोषणा का कतिपय परिस्थितियों में शून्य होगा:—(1) जहां अधिनियम की धारा 245न के अधीन अभ्यावेदन आयुक्त द्वारा या अन्यथा प्राधिकरण को किया जाता है कि उसके द्वारा धारा 245द की उपधारा (6) के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय आवेदक द्वारा कपट या तथ्यों के दुर्व्यपदेशन से अभिप्राप्त किया गया है, ऐसा अभ्यावेदन चार प्रतियों में किया जाएगा और उसके साथ कपट या दुर्व्यपदेशन को सम्मिलित करते हुए तथ्यों के एक विवरण तथा कपट या दुर्व्यपदेशन के तथ्यों के दावे को सिद्ध करने के लिए साक्ष्य की विशिष्टियां भी होंगी।
- (2) ऐसे अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर एक सूचना खंडन के लिए अभ्यावेदन की प्रति के साथ आवेदक को जारी की जाएगी और धारा 245न के अधीन आदेश पारित करने से पहले आवेदक और आयुक्त को सुने जाने के लिए उचित अवसर अनुज्ञात किया जाएगा।
- 24. कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होना: प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होंगी और आवेदक, आयुक्त या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से भिन्न कोई व्यक्ति प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना ऐसी कार्यवाहियों के दौरान उपस्थित नहीं रहेगा।
- 25. आदेशों का प्रकाशन:—प्राधिकरण के ऐसे आदेश, जिन्हें अध्यक्ष किसी प्राधिकृत रिपोर्ट या प्रेस में प्रकाशन के लिए ठीक समझें, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो अध्यक्ष विनिर्दिष्ट करे, प्रकाशन के लिए जारी किए जा सकेंगे।
- 26. आदेशों का अधिप्रमाणन और संसूचना:—(1) अध्याय 19-ख के अधीन प्राधिकरण का प्रत्येक आदेश सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से इस्ताक्षरित होगा और उस पर प्राधिकरण की प्राधिकारिक मुद्रा होगी।
- (2) प्राधिकरण के ऐसे आदेश की एक प्रमाणित प्रति सचिव के या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन जिस पर प्राधिकरण की प्राधिकारिक मुद्रा होगी, आवेदक और आयुक्त को संसूचित की जाएगी।
- 27. प्राधिकरण की कार्यवाहियां:—(1) जब अध्यक्ष से भिन्न प्राधिकरण का एक या दोनों सदस्य अनुपस्थिति, रूग्णता के कारण या किसी अन्य कारण से या सदस्यों के पद में कोई रिक्ति या रिक्तियां होने की दशा में, अपने कृत्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो और मामला किसी कारण से स्थिगित नहीं किया जा सकता हो तो अकेला अध्यक्ष या अध्यक्ष और शेष सदस्य प्राधिकरण के रूप में कृत्य करेगा।
- (2) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि आवेदन की सुनवाई कर रहे सदस्यों में मतभेद हो, तो सदस्यों की बहुसंख्या की राय अभिभाव होगी और प्राधिकरण के आदेशों को बहुसंख्या के विचार के रूप में अभिव्यक्त किया जाएगा किन्तु संख्या के विचार से भिन्न राय रखने वाले कोई सदस्य अपने कारणों को अलग से अभिलिखित कर सकेगा।
- (3) जहां उपनियम (1) के अधीन अध्यक्ष और एक अन्य सदस्य मामले की सुनवाई करें और अपनी राय में बंटे हुए हों वहां अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी।
- 28. अन्य आवेदनों के मामले में प्रक्रिया: इन नियमों में धारा 245थ(1) के अधीन आवेदन की सुनवाई और निपटारे के लिए अन्तर्विष्ट उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सिंहत प्राधिकरण के समक्ष सभी अन्य आवेदनों, अर्जियों, अन्य अभ्यावेदनों की सुनवाई और निपटारे को लागू होंगे।

- 29. पोशाक विनियम:—(1) प्राधिकृत प्रतिनिधि प्राधिकरण के समक्ष सक्षम वृत्तिक निकाय, यदि कोई हो, द्वारा अपने वृत्ति के सदस्यों के लिए विहित पोशाक में उपसंजात होगा।
- (2) प्राधिकृत के समक्ष उपसंजात होने वाले सभी व्यक्ति समुचित रूप से पोशाक पहने होंगे।

[फा. सं. ए.ए.आर./074/1996]

आर.पी.एम. त्रिपाठी, सचिव अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण

MINISTRY OF FINANCE AUTHORITY FOR ADVANCE RULINGS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1996

The Authority for Advance Rulings (Procedure) Rules, 1996

- G.S.R. 426(E).—In exercise of the powers conferred by Section 245V of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Authority for Advance Rulings hereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short title and commencement:—(1) These rules may be called the Authority for Advance Rulings (Procedure) Rules, 1996.
 - (2) They shall come into force with immediate effect.
- 2. **Definitions**:—In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (b) "Advance Ruling" means an advance ruling as defined in sub-clause (a) of section 245N of the Act;
 - (c) "Applicant" means an applicant as defined in subclause (b) of section 245N of the Act;
 - (d) "Application" means an application under sub-section (1) of section 245Q of the Act but shall include, where the context permits, all applications, petitions and representations of the nature referred to in rule 5:
 - (c) "Authorised Representative"
 - (i) in relation to an applicant shall have the meaning assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Act as if the applicant were an assessee;
 - (ii) in relation to the Commissioner, means a person authorised by the Commissioner in writing to appear, plead and act for the Commissioner in any proceedings before the Authority;
 - (f) "Authority" means the Authority for Advance Rulings constituted under Section 245-O of the Act;
 - (g) "Case" means any proceedings under Chapter XIX-B of the Act in respect of an applicant;
 - (h) "Chairman" means the Chairman of Authority;

- (i) "Commissioner" means,—
 - (1) the Commissioner as defined in sub-clause (16) of section 2 of the Act in respect of an applicant assessed under the Income-tax Act,
 - (2) the Commissioner designated by the Central Board of Direct Taxes in this behalf in respect of an applicant not hitherto assessed,
- (j) "Member" means a member of the Authority and includes the Chairman;
- (k) "Order" includes any order, direction or ruling of the Authority;
- (l) "Rule" means a Rule of the "Authority for Advance Rulings (Procedure) Rules, 1996";
- (m) "Secretary" means a Commissioner of Income-Tax designated as the Secretary of the Authority and includes an Additional Commissioner of Income-tax and Deputy Commissioner of Income-tax appointed to assist the Secretary in his functions where the context so requires;
- (n) "Section" means a section of the Act;
- (o) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Language of the Authority:—(1) The language of the Authority shall ordinarily be English:

Provided that the Authority may, at the request of the parties, permit the use of Hindi in the proceedings before it to the extent it may consider appropriate and practical.

- (2) Where any document is in a language other than English or Hindi, an English translation thereof should also be filed along therewith.
- (3) The ruling of, and other orders passed by the Authority may, at the discretion of the Authority, be in Hindi or English.
- 4. Sittings of the Authority:—The Authority shall hold its sittings at its headquarters at Delhi or at such other place or places as may be authorised by the Chairman and the date and place of hearing shall be notified in such manner as the Chairman may by general or special order direct.
- 5. Powers of the Authority:—The Authority shall hear and determine the application made under sub-section (1) of section 245Q of the Act and such other applications, petitions and representations of an interlocutory, incidental or ancillary nature as may be necessary for a complete and effective disposal of the application, as the Chairman may by general or special order direct.
- 6. Power to remove difficulty:—If any difficulty arises in giving effect to any order of the Authority, the Authority may, on its own motion or on an application made by the applicant or the Commissioner, remove the difficulty in so far as it is not inconsistent with the provisions of the Act.
- 7. Powers and functions of the Secretary:—(1) The Secretary shall have the custody of the records of the Authority and shall exercise such other functions as are assigned

57-57 C. / 145-2

to him under these rules or by the Chairman by separate order.

- (2) The official seal of the Authority shall be kept in custody of the Secretary.
- (3) The Secretary shall also have the following powers and duties namely:—
 - (i) to receive all applications filed before the Authority;
 - (ii) to scrutinise the application to find out whether they are in conformity with the Act, the rules and the procedure;
 - (iii) to point out defects in such application to the parties and require them to remove the defects by affording them a reasonable opportunity to do so and, where, within the time granted, the defects are not removed, to obtain necessary orders of the Authority;
 - (iv) to fix the date of hearing for the application in consultation with the Chairman and direct the issue of notices therefor;
 - (v) To issue the service of notices or other processes and to ensure that the parties are properly served;
 - (vi) to requisition records from the custody of any person including a Commissioner or any other authority;
 - (vii) to allow inspection of records of the Authority;
 - (viii) to direct any formal amendment of the records of the Authority;
 - (ix) to grant certified copies of the orders of the Authority to the parties;
 - (x) to grant certified copies of documents filed in the proceedings to the parties in accordance with the rules;
 - (xi) to bring on record legal representatives, in case of death or retirement of any party to the proceedings and to make such appropriate amendments in the cause title as may become necessary in the other situations referred to in rule
- 8. Signing of Notices Etcetera:—(1) Any requisition, direction, letter, authorisation, or written notice to be issued by the Authority shall be signed by the Secretary or by an officer authorised by him.
- (2) Nothing in sub-rule (1) shall apply to any requisition or direction which the Authority may, in the course of the hearing, issue to an applicant or a Commissioner or an authorised representative.
- 9. Mode of Service of Notices:—Every notice or other document required to be served on or delivered to any person may, be sent by hand through process server, or by registered post or by FAX to that person or his authorised representative at the address or FAX number furnished by him for service or at the place where the person or his authorised representative ordinarily resides or carries on business or personally works for gain.

- 10. Procedure for filing applications:—(1) An application shall be made in Form 34C of the Income-tax Rules, 1962 in quadruplicate and presented by the applicant in person or by an authorised representative to the Secretary or any other officer notified in writing by the Secretary or sent by registered post addressed to the Secretary along with a fee of two thousand five hundred Indian Rupees in the form of a Demand Draft drawn in favour of "Authority for Advance Rulings" payable at New Delhi.
- (2) The application, its verification and the annexures, statements and documents accompanying it, shall be signed in the manner set out in sub-rule (2) of rule 44E of the Income-tax Rules, 1962:

Provided that where a person signing the application and other documents claims to have been duly authorised in that behalf under the rules, the application shall be accompanied by a power of attorney, authorising him to append his signature and an affidavit setting out the unavoidable reason which entitles him to sign it.

- (3) An application sent by registered post under subrule (1) shall be deemed to have been made on the date on which it is received in the office of the Authority.
- (4) If the applicant is not hitherto assessed in India, he shall indicate in Annexure I to the application:
 - (a) his head office in any other country,
 - (b) the place where his office and residence is located or is likely to be located in India, and
 - (c) the name and address of his representative in India, if any, authorised to receive notices and papers and act on his behalf.
- (5) The Secretary may send the application back to the applicant if it is defective in any manner for removing the defects within such time as he may allow. Such application shall be deemed to have been made on the date when it is represented after correction.
- 11. Submission of Additional facts before the Authority:—(1) The Authority may at its discretion permit or require the applicant to submit such additional facts as may be necessary to enable it to pronounce its advance ruling.
- (2) Where in the course of the proceedings before the Authority, a fact is alleged which cannot be borne out by or is contrary to the record, it shall be stated clearly and concisely and supported by a duly sworn affidavit.
- 12. Questions contained in the application:—The applicant shall not, except by leave of the Authority, urge or be heard in support of any additional question not set-forth in the application, but in deciding the application of the Authority shall at its descretion consider all aspects of the questions set-forth as may be necessary to pronounce a ruling on the substance of the questions posed for its consideration.
- 13. Date and place of Hearing to be notified:—
 (1) Where an application under section 245Q is received from an applicant not hitherto assessed and there is no Commissioner designated in respect thereof under rule 2(i)(2), a copy

of the application and enclosures thereto shall be forwarded to the Board calling upon it to specify or designate, within a period of two weeks, the Commissioner for the purposes of the application, failing which the application may be decided without hearing the Commissioner.

- (2) On receipt of an application under section 245Q in respect of which there is a Commissioner as defined in rule 2(i)(1) or a Commissioner has been designated by the Board under rule 2(i)(2) or under sub-rule (1) of this rule, the Authority shall notify the applicant and the Commissioner of the date and place of hearing of the application and forward a copy of the application to the Commissioner calling upon him to furnish the relevant records of the case along with his comments, if any, on the contents of the application and nominate his authorised representative if he desires to be heard.
- 14. Authorisation to be filed:—An authorised representative appearing for the applicant at the hearing shall file, before the commencement of the hearing, a document authorising him to appear for the applicant and if he is a relative of the applicant, the document shall state the nature of his relationship with the applicant, or if he is a person regularly employed by the applicant the capacity in which he is at the time employed.
- 15. Continuation of proceedings after the death Etc. of the applicant:—Where the applicant dies or is wound up on dissolved or disrupted or amalgamated or succeeded to by any other person or otherwise comes to an end, the application shall not abate and may be permitted by the Authority, where it considers that the circumstances justify it, to be continued by the executor, administrator or other legal, representative of the applicant or by the liquidator, receiver or assignee, as the case may be, on an application made in this behalf.
- 16. Hearing of application:—(1) On the day fixed, or any other day to which the hearing may be adjourned, the Authority shall hear the applicant or his authorised representative in cases where it is proposed to reject the application or the applicant seeks/has sought an opportunity of being heard. The Authority may also hear the Commissioner or his authorised representative as well if it considers it necessary before pronouncing its advance ruling.
- (2) In appropriate cases the Authority may call upon any person to supply such material as it may consider necessary to assist the Authority in arriving at a decision.
- (3) The Authority may, on such conditions as the circumstances of the case may be require, adjourn the hearing of the application.
- 17. Hearing of application Ex-parte: —Where on the date fixed for hearing or any other day to which the hearing may be adjourned, the applicant or the Commissioner does not appear in person or through an authorised representative when called on for hearing, the Authority may dispose of the application ex-parte on merits:

Provided, that where an application has been disposed of as above and the applicant or the Commis-

- sioner, as the case may be, applies within 15 days of receipt of the order and satisfies the Authority that there was sufficient cause for his non-appearance when the application was called upon for hearing, the Authority may, after allowing the opposite party a reasonable opportunity of being heard, make an order setting aside the ex-parte order and restore the application for fresh hearing.
- 18. Modification of the Order:—Where the Authority finds suo motu or on a representation made to it by the applicant or the Commissioner or otherwise, but before the ruling pronounced by the Authority has been given effect to by the assessing officer, that there is a change in law of facts on the basis of which the ruling was pronounced, it may by order modify such ruling in such respects as it considers appropriate, after allowing the applicant and the Commissioner a reasonable opportunity of being heard.
- 19. Rectification of Mistakes:—(1) The Authority may, with a view to rectifying any mistake apparent from the record, amend any order passed by it before the ruling pronounced by the Authority has been given effect to by the assessing officer.
- (2) Such amendment may be made suo motu or when the mistake is brought to its notice by the applicant or the Commissioner, but only after allowing the applicant and the Commissioner reasonable opportunity of being heard.
- 20. Amendment of the Record:—If at any stage of the proceedings before the Authority it appears that there is any factual or material error in the records the same shall be amended after hearing the applicant and the Commissioner.
- 21. Fees for supply of additional certified copies:—
 (1) The Secretary may order grant of additional certified copies of documents or orders to the applicant or the Commissioner on a written request made by either of them.
- (2) Copying fees for supply of additional certified copies to the applicant shall be charged at rupees three per page and such fees shall be paid in advance in cash.
- 22. Inspection of records and fees thereof:—(1) The applicant or the Commissioner or an authorised representative may be allowed to inspect the records of the case on making an application in writing to the Secretary provided that only those documents shall be allowed to be inspected which have been relied upon in the proceedings before the Authority.
- (2) The inspection shall be allowed only in the presence of an officer of the Authority and the applicant may be permitted to make notes of inspection but not to take copies of any document.
- (3) Fees for inspecting records of the Authority shall be charged from the applicant as follows:
 - (a) Rupees one hundred for the first hour or part thereof and
 - (b) Rupees fifty for every additional hour or part thereof.

- (4) Fees for inspection shall be paid in advance in cash.
- 23. Declaration of advance rulings to be void in certain circumstances:—(1) Where a representation is made under section 245T of the Act to the Authority by the Commissioner or otherwise that an advance ruling pronounced by it under sub-section (6) of section 245R has been obtained by the applicant by fraud or misrepresentation of facts, such representation shall be made in quadruplicate and shall be accompanied by a statement of facts incorporating the fraud of misrepresentation as also particulars of the evidence to substantiate the claim of fraud or misrepresentation of facts.
- (2) On receipt of such representation a notice shall be issued to the applicant along with a copy of the representation for rebuttal and a reasonable opportunity shall be allowed to the applicant and the Commissioner for being heard before passing an order under Section 245T.
- 24. Proceedings not open to the Public:—Proceedings before the Authority shall not be open to the public and no person, other than the applicant, the Commissioner or their authorised representatives shall, without the permission of the Authority, remain present during such proceedings.
- 25. Publication of Orders:—Such of the orders of the Authority, as the Chairman deems fit for publication in any authoritative report or the press, may be released for such publication on such terms and conditions as the Chairman may specify.
- 26. Authentication and Communication of Orders:—(1) Every order of the Authority under Chapter XIX-B shall be duly signed by the members and bear the official seal of the Authority.
- (2) One certified copy of such order of the Authority shall be communicated to the applicant and the Commissioner under the signature of the Secretary or any other officer of the Authority authorised by him in this behalf and bear the official seal of the Authority.

- 27. Proceedings of the Authority:—(1) When one or both of the members of the Authority other than the Chairman is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause or in the event of occurrence of any vacancy or vacancies in the office of the members and the case cannot be adjourned for any reason, the Chairman alone or the Chairman and the remaining member may function as the Authority.
- (2) Subject to the provisions of sub-rule (3), in case there is difference of option among the members hearing an application the opinion of the majority of members shall prevail and orders of the Authority shall be expressed in terms of the views of the majority but any member dissenting from the majority view may record his reasons separately.
- (3) Where the Chairman and one other member hear a case under sub-rule (1) and are divided in their opinion, the opinion of the Chairman shall prevail.
- 28. Procedure in case of other application:—The provisions contained in these rules for the hearing and disposal of application under section 245Q(1) shall apply, mutatis mutandis, to the hearing and disposal of all other applications, petitions and representations before the Authority.
- 29. Dress Regulations:—(1) An authorised representative shall appear before the Authority in dress prescribed for the members of his profession by the competent professional body, if any.
- (2) All other persons appearing before the Authority shall be properly dressed.

[F. No. AAR/074/1996]

R.P.M. TRIPATHI, Secy. Authority for Advance Rulings